and the other at Vijayawada. These centres are collecting daily prices, arrival of various fruits and vegetables and disseminate the same through various mass media such as newspapers, All India Radio and Doordarshan Kendras. The Directorate of Marketing and Inspection had provided financial grant-in-aid to 138 markets in the state of Andhra Pradesh to the tune of Rs. 3.55 crores from 1975-76 to 1992-93 to strengthen infrastructural facilities and propagate post harvest technology. Out of this amount, Rs. 15 lakh were provided for the infrastructure development of fruits and vegetable markets in Hyderabad. The scheme has since been transferred to the State Government.

(d) and (e) The National Horticulture Board is providing financial assistance to government agencies/cooperative societies and other voluntary organisations to strengthen post harvest and marketing infrastructure for horticulture crops under "the strengthening post harvest structure for horticulture crops" scheme. Under this scheme, provision is made to provide assistance for pre-cooling units, transport vehicles, plastic crates, retail outlets and packing grading centres etc. During 1993-94, an amount of Rs. 3.95 lakh was provided to Andhra Pradesh and during the current year of 1994-95, an assistance of Rs. 65 lakhs is proposed in this state for strengthening post harvest infrastructural facilities. The Directorate of Marketing and Inspection also conducts various trials on transportation, packing, storage and grading of horticultural crops to improve their post harvest.

मिट्टी के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करना

1557. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी, जलवायु आदि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी थी और ये किस-किस राज्य में स्थित थे ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के बारे में प्रचार करने के लिए उनके मानचित्र प्रकाशित किए गए थे ताकि ग्राम किसान इससे लाभान्वित हो सकें ;

(घ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में अधिक पैदावार देने वाली फसलों के प्रचार की कोई व्यवस्था की है ;

(ङ) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा उक्त व्यवस्था की योजना और मानचित्रों के प्रकाशन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना, ब्यूरो देश के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मानचित्र तथा विभिन्न राज्यों के मृदा संसाधन मानचित्र को तैयार करने में लगा हुआ है। देश का एक 20 क्षेत्रीय कृषि परिस्थिति की मानचित्र 1:5 मिलियन स्केल में प्रकाशित किया गया है। कृषि परिस्थितिकी क्षेत्रों की सीमाएं एक राज्य से दूसरे राज्य तक चली जाती हैं। राज्यों के साथ इन क्षेत्रों की सूची नीचे दी

रही है :—

(1)	ए इ आर–1 (कृषि पारिस्थिति क्षेत्र)	: जम्मू तथा कश्मीर
(2)	ए इ आर–2	: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
(3)	ए इ आर–3	: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
(4)	ए इ आर–4	: गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश
(5)	ए इ आर–5	: गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीव
(6)	ए इ आर–6	: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
(7)	ए इ आर–7	: आन्ध्र प्रदेश
(8)	ए इ आर–8	: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
(9)	ए इ आर–9	: बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब, जम्मू व कश्मीर
(10)	ए इ आर–10	: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
(11)	ए इ आर–11	: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश
(12)	ए इ आर–12	: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पं० बंगाल
(13)	ए इ आर–13	: बिहार, उत्तर प्रदेश
(14)	ए इ आर–14	: जम्मूयब कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
(15)	ए इ आर–15	: असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
(16)	ए इ आर–16	: अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल
(17)	ए इ आर–17	: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा
(18)	ए इ आर–18	: आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
(19)	ए इ आर–19	: गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र दमन व गोवा
(20)	ए इ आर–20	अंडमान तथा निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह

विभिन्न राज्यों के मृदा संसाधन मानचित्र 1 : 250,000 स्केल पर तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) राज्य विकास अभिकरणों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि को प्रतियां वितरित करके कृषि पारिस्थितिकी मानचित्र का व्यापक रूप से प्रचार किया गया है । ये मानचित्र क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर के नियोजन के लिए उपयोगी होंगे ।

(घ) और (ङ) जी हां । राज्यों के विस्तार अभिकरण दिये गये कृषि जलवायु-संबंधी क्षेत्र में फसल उगाने की उपलब्ध अवधि (लैन्थ) को ध्यान में रखते हैं तदनुसार सिंचित तथा बारानी कृषि दोनों के लिए फसलों की उपर्युक्त किस्मों को प्रोत्साहन देते हैं । यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम का एक समाकलित भाग भी बनता है ।

(च) वर्ष 1993–94 के दौरान राज्य मृदा संसाधन मानचित्रों के मुद्रण का कार्य शुरू नहीं किया गया था ।